



# भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)

PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 2855]

नई दिल्ली, शुक्रवार, अक्टूबर 6, 2017/आश्विन 14, 1939

No. 2855]

NEW DELHI, FRIDAY, OCTOBER 6, 2017/ASVINA 14, 1939

## सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय

(सामाजिक न्याय और अधिकारिता विभाग)

(पिछड़ा वर्ग प्रभाग)

आदेश

नई दिल्ली, 6 अक्टूबर, 2017

**का.आ. 3264(अ).**—जबकि राष्ट्रपति ने भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग-II, धारा 3(ii) में प्रकाशित दिनांक 02 अक्टूबर, 2017 के का.आ. 3210(अ) के द्वारा अन्य पिछड़े वर्गों के उप-श्रेणीकरण की जांच करने के लिए अन्य पिछड़े वर्गों के लिए एक आयोग गठित किया है।

जबकि केन्द्र सरकार, आयोग की स्थापना तथा आयोग के अध्यक्ष एवं सदस्यों के कार्यकाल के संबंध में, उपर्युक्त आदेश के अनुसरण में कतिपय दिशा-निर्देश विनिर्दिष्ट करना आवश्यक समझती है।

### I. आयोग की स्थापना –

- यह आयोग, अन्य पिछड़ा वर्गों के उप-श्रेणीकरण की जांच करने वाले आयोग के रूप में जाना जाएगा। इस आयोग के अध्यक्ष का दर्जा केन्द्र सरकार के राज्य मंत्री के स्तर का होगा।
- पदेन सदस्यों के अलावा, आयोग के सदस्य (सदस्यों) का दर्जा भारत सरकार के सचिव के स्तर का होगा।
- आयोग का मुख्यालय नई दिल्ली में स्थित होगा।
- इस आयोग की स्थापना लागत का विनियोजन मुख्य शीर्ष 2225 उप-मुख्य शीर्ष 03- लघु शीर्ष 03-001 द्वारा राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग को सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय द्वारा किए गए बजटीय अनुदान से किया जाएगा।

### II. पद का निबंधन और शर्तें

अध्यक्ष और सदस्य का कार्यकाल आयोग के अध्यक्ष के कार्यभार संभालने की तारीख से 12 सप्ताह की अवधि तक रहेगा।

- जबकि अध्यक्ष, उच्च न्यायालय के सेवानिवृत्त मुख्य न्यायाधीश है वह न्यायालय के न्यायाधीश के लिए अनुमत्य वेतन पाने के पात्र होंगे। अध्यक्ष को देय अन्य सुविधाएं वही होंगी जिनका निर्धारण भारत सरकार द्वारा किया गया हो।
- पदेन सदस्य के अलावा, सदस्य को देय वेतन, भत्ते और अन्य सुविधाएं ऐसी होंगी जो भारत सरकार द्वारा निर्धारित की गई हों।

**III. त्यागपत्र और पद से हटाना**

- (क) अध्यक्ष तथा सदस्य राष्ट्रपति को संबोधित अपने हस्ताक्षर सहित लेख द्वारा सूचना देकर अपने पद का त्याग कर सकते हैं।
- (ख) राष्ट्रपति अध्यक्ष/सदस्य को आदेश द्वारा पद से हटा सकते हैं यदि वह व्यक्ति—
- अनुन्योचित दिवालिया हो जाता है; अथवा
  - अपने कार्यकाल की अवधि के दौरान अपने कर्तव्यों/अपने कार्यालय से बाहर किसी सवेतनिक रोजगार में लगा हुआ है; अथवा
  - राष्ट्रपति की राय में, मानसिक अथवा शारीरिक अक्षमता के कारण पद पर बने रहने के लिए अनुपयुक्त हो; अथवा
  - किसी ऐसे अपराध के लिए दोषसिद्ध अथवा कारावास से दण्डित किया गया हो, जिसमें राष्ट्रपति की राय में नैतिक अक्षमता अन्तर्बलित हो; अथवा
  - कार्य करने से इंकार करता है; अथवा
  - राष्ट्रपति की राय में अध्यक्ष या सदस्य के पद का ऐसा दुरुपयोग करता है जिसके कारण उस व्यक्ति का पद पर बने रहना आयोग के हित में हानिकारक हो;
- बशर्ते कि अध्यक्ष अथवा सदस्य को तब तक नहीं हटाया जाएगा जब तक कि उन्हें उस मामले में सुनवाई का एक समुचित अवसर न दिया गया हो।

[फा. सं. 12015/9/2017-बीसी-II]

बी. एल. मीना, संयुक्त सचिव

**MINISTRY OF SOCIAL JUSTICE AND EMPOWERMENT****(Department of Social Justice and Empowerment)****(BC DIVISION)****ORDER**

New Delhi, the 6th October, 2017

**S.O. 3264(E).**—Whereas President has constituted a Commission for Other Backward Classes to examine sub-categorization of Other Backward Classes *vide* S.O. 3210(E), dated 2nd October, 2017 published in the Gazette of India Extraordinary Part-II-Section 3 (ii).

Whereas the Central Government considers it necessary to specify certain guidelines in pursuance of the above cited order, with regard to the establishment of the Commission and term of office of the Chairperson and Members of the Commission.

**I. Establishment of the Commission—**

- The Commission shall be known as the Commission to examine the sub-categorization of Other Backward Classes. The Chairperson of the Commission will have the status of a Minister of State of the Central Government.
- The Member (s) of the Commission other than ex-officio Members will have the status of Secretary to the Government of India.
- The headquarters of the Commission will be located at New Delhi.
- The establishment cost of the Commission shall be appropriated from the budgetary grants made by the Ministry of Social Justice and Empowerment to the National Commission for Backward Classes *vide* Major head 2225 sub-Major head 03- Minor Head 03-001

**II. Terms and Condition of Office**

The Chairperson and Members shall hold office for a period of 12 weeks from the date of assumption of charge by the Chairperson of the Commission.

- i. Whereas the Chairperson, being a retired Chief Justice of the High Court shall be entitled to such pay as admissible to a judge of the High Court. The other facilities due to the Chairperson shall be as determined by the Government of India.
- ii. The status salaries, allowances and other facilities due to the Member other than Ex officio Member shall be as determined by the Government of India.

**III. Resignation and Removal**

(a) The Chairperson and Member may by notice in writing under his/her hand addressed to the President, resign from his/her post.

(b) The President may by order remove from office the Chairperson / Member if he/she:—

- (i) is adjudged as an insolvent; or
- (ii) is engaged during his/ her term of office in any paid employment outside the duties of his/ her office; or
- (iii) is, in the opinion of the President, unfit to continue in office by reason of infirmity of mind or body; or
- (iv) is convicted and sentenced to imprisonment for an offence, which in the opinion of the President, involves moral turpitude; or
- (v) refuse to act; or
- (vi) in the opinion of the President has so abused the position of the Chairperson, or a Member as to render that person's continuance in office detrimental to the interest of the Commission;

Provided that the Chairperson or Member shall not be removed until he/she has been given a reasonable opportunity of being heard in the matter.

[F. No. 12015/9/2017-BC-II]

B. L. MEENA, Jt. Secy.